बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 255 ● नई दिल्ली ● बुधवार 29 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष से शिक्षा मंत्री ने की शिष्टाचार भेंट

चंडीगढ़ । हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने आज यहां लोक भवन में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल और शिक्षा मंत्री के बीच हरियाणा के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता, सुलभता तथा समग्र विकास को और सुदृढ़ बनाने संबंधी मुद्दों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया। राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने राज्यपाल को अवगत कराया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक जनहितकारी पहल कर रही है।

संसद: प्रियंका ने उठाया जंतर-मंतर पर लाठीचार्ज का मुद्दा, कहा- पीएम मोदी कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदले

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। संसद में प्रियंका गांधी ने कहा कि बच्चों पर लाठियां किसके आदेश पर चलाए गए, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है, अध्यापक, छात्र, माता-पिता पूछ रहे हैं सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछ रही है। ये सदन सांसदों की जागीर नहीं है। मंगलवार को संसद में प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत एक घटना से की । जब मैं एक घायल छात्रा से मिलने गए, तो उसकी मां बोलीं- सुबह से बड़े-बड़े नेता आए। वह भी आए जिनकी वजह से बेटी का यह हाल हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं- क्या जरूरत थी, बच्ची पर ज्यादती करने की। देश के युवाओं पर पैलेट गन चलवाने की क्या जरूरत थी।

छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है?- प्रियंका

प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। प्रियंका गांधी ने पूछा कि छात्रों पर आंसु गैस के गोले क्यों छोड़े गए और लाठीचार्ज क्यों किया गया। क्या छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? उन्होंने युवा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जताई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। प्रियंका गांधी ने संसद में सरकार पर तीखा हमला करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि हम बार-बार सवाल कर रहे हैं कि इस कार्रवाई की अनुमति किसने दी और क्या यह आदेश प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की ओर से आया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के छात्र, उनके माता-पिता और शिक्षक इस मामले में जवाब चाहते हैं। संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक जवाबदेही का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के सेवक होते हैं, शासक नहीं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। ऐसे में उन्हें न्याय, पारदर्शिता और सम्मान मिलना चाहिए।

भरोसा दोबारा बनाने के लिए उसी सिस्टम से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता- प्रियंका

प्रियंका गांधी ने कहा, 'इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टरों को लगातार कमजोर किया है। पेपर लीक से करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन एक भी दोषी को सजा नहीं मिली। शिक्षण संस्थानों

में संघ के प्रचारकों को भर-भरकर नियुक्त किया गया और संस्थाओं को खोखला बना दिया गया। एनटीए बनाकर परीक्षा प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। हर साल शिक्षा बजट की हिस्सेदारी घटती चली गई। शिक्षा बजट उससे भी कम है, जितना पूंजीपतियों के लोन माफ किए गए हैं। सोचिए, सरकार की प्राथमिकता क्या है। उन्होंने आगे कहा, देश के युवाओं का भरोसा इस सिस्टम से टूट चुका है। भरोसा दोबारा बनाने के लिए उसी सिस्टम से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता। इसके लिए सिस्टम के दायरे से बाहर निकलकर ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री और उनके साथी क्या सोच रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने शर्मनाक परिस्थितियों में इस्तीफा दिया और संसद में उनका ऐसा स्वागत किया गया, जैसे कोई सुपरस्टार आया हो। कल जब उन्हें मुकुट पहनाया जा रहा था, उसी समय महाराष्ट्र का एक परिवार अपनी बेटी की आत्महत्या का मातम मना रहा था। जहां शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी से स्वागत किया जा रहा है। ऐसे में कोई आप पर कैसे यकीन करे। उन्होंने आगे आरोप लगाया, प्रधानमंत्री ने नए शिक्षा मंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुना, जिन्होंने एक गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता के दोषियों की रिहाई पर सहमति जताई थी। इस टिप्पणी पर स्पीकर ने प्रियंका गांधी को टोका और सत्तापक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा, 'प्रियंका गांधी ने हमारे नए शिक्षा मंत्री पर जो टिप्पणी की है, वह एक तरह से चरित्र हनन है। हम ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं करते। इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाया जाए। संसद में बहस का स्तर नहीं गिराना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। यदि वह अपने आरोप को प्रमाणित नहीं कर सकतीं, तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए।

प्रियंका गांधी की टिप्पणी को लेकर ट्रेजरी बेंच का विरोध

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और प्रह्लाद जोशी ने कहा, पहले बयान को ऑथेंटिकेट (प्रमाणित) किया जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए।इस पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, निशिकांत दुबे ने इसी सदन में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को लेकर भी टिप्पणियां की थीं, लेकिन उन्हें रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, मैं सदन में मौजूद हूं। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया। मैं इस बयान का खंडन करता हूं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।इसके बाद प्रियंका गांधी ने अखबार की एक कटिंग सदन के पटल पर रखते हुए कहा, क्या जोशी जी अपने इस बयान का खंडन कर रहे हैं? क्या आप इसका खंडन कर रहे हैं? इस दौरान स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, सदन में केवल इस विधेयक (बिल) पर ही चर्चा होगी। प्रियंका गांधी ने कहा, आज हम इस सदन में ऐसे संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं, जो 2024 में ही पारित हो चुका है। जब से यह कानून लागू हुआ है, तब से एक भी आरोपी को सजा नहीं मिली है। उन्होंने कहा, पिछले दो दिनों से छात्रों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के आरोपियों के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदलने चाहिए। नई-नई समितियां बनाने से काम नहीं चलेगा। पहले भी राधाकृष्णन समिति बनाई गई थी। उस समिति में तो गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। उन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता। इस टिप्पणी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मुस्करा पड़े।

'प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा'

उन्होंने आगे कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी देख लीजिए। कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील ही पेश नहीं हुआ। जेनजी का भरोसा जीतने के लिए नए-नए एंगल के वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रियंका गांधी ने कहा, 'पुलिस की लाठी बच्चों की पीठ पर नहीं, सरकार की साख पर पड़ी है। अपनी साख बचाइए। आपके शासन में बड़ी-बड़ी चोरियां हुई हैं। चुनाव में वोट की चोरी, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी तब हुई, जब देश के नौजवानों का भविष्य और उनके सपने चुरा लिए गए।उन्होंने कहा, 'अगर देश का युवा निराश हो गया और उसकी उम्मीद टूट गई, तो वह भारत की हार होगी। भारत की हार होगी तो हम विपक्ष के लोग जान भी दे देंगे।

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एलान: 'लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500

नई दिल्ली । दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में बहुप्रतीक्षित 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राजधानी की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 2500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस अहम फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि आज बहुत खुशी का पल है। जो वादा हमने दिल्ली की अपनी बहनों से किया था, उसे आज हमारी कैबिनेट ने पूरा कर दिया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के सुचारू आवेदन के लिए 1 अगस्त से एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि प्राप्त होने वाले आवेदनों के सत्यापन का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, ताकि रक्षाबंधन (राखी) के पावन पर्व तक महिलाओं के बैंक खातों में योजना की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाए।

योजना के लिए पात्रता और शर्तें

सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी।

-आवेदक महिला को आवेदन करते समय एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।

-महिला को इस पत्र में यह प्रमाणित करना होगा कि वह कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी है।

-आवेदक महिला का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

महिलाओं में योजना को लेकर उत्साह

दिल्ली सरकार का यह फैसला महिला सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। रक्षाबंधन से पहले हुई इस घोषणा से राजधानी की महिलाओं में भारी उत्साह है। यह मासिक सम्मान राशि उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।

स्वाति मालीवाल का केजरीवाल पर गंभीर आरोप: बोलीं- पंजाब में हुए छह पेपर लीक, सीजेपी को बताया आप की 'बी टीम'

नई दिल्ली ।

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में पेपर लीक मामलों को लेकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में पंजाब में छह बड़े पेपर लीक हुए, लेकिन केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप हैं। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मालीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों में पंजाब में छह बड़े पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई परीक्षाओं में नकल के भी आरोप लगे हैं। मालीवाल के अनुसार, 19 जुलाई को हुई फार्मेसी परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर नकल हुई थी। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पेपर लीक के आरोपों से इनकार किया है। मालीवाल ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को आम आदमी पार्टी की 'बी टीम' बताते हुए आरोप लगाया कि इस पार्टी का गठन केजरीवाल के सहयोगियों ने उनके पैसे से किया है। उन्होंने कहा, सीजेपी आम आदमी पार्टी की बी टीम है। इसे केजरीवाल के सहयोगियों ने बनाया है और इसके लिए उन्हीं का पैसा लगा है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने सीजेपी के लिए बड़े स्तर पर पेड पीआर अभियान भी चलाया। लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो न सीजेपी बोलती है और न ही अरविंद केजरीवाल।' मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोलते और इससे बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल रोज लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील करते हैं, लेकिन पंजाब में पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कराया जाता है। मालीवाल ने कहा, 'अरविंद केजरीवाल खुद को पंजाब का 'सुपर मुख्यमंत्री' बना चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है।' पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया, 'पंजाब के मुख्यमंत्री पूरे दिन नशे में रहते हैं और बेबुनियाद व असंगत बयान देते हैं।' उन्होंने मांग की कि पंजाब के शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल, अब बहुत हो चुका।'

दिल्ली में तीन मंजिला इमारत झुकी: कभी भी हो सकता है हादसा, लोगों में खौफ; बोले- शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई

नई दिल्ली । दिल्ली के गीता कॉलोनी के 2ए ब्लॉक में एक तीन मंजिला इमारत के झुक जाने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है। घटना स्थल पर आपदा प्रबंधन दल और पुलिस पहुंच गए हैं, और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इमारत के झुकाव को लेकर स्थानीय लोगों ने पहले भी कई बार शिकायतें की थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। इलाके के निवासी राकेश ने कहा, 'यह इमारत काफी समय से झुकी हुई है। कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ऊपर से एक स्लैब गिर गया। शिकायतें तो की गईं, लेकिन समस्या तब से है जब बिल्डरों ने यह संपत्ति खरीदी थी। बिल्डरों ने पूरी इमारत को तोड़कर दोबारा नहीं बनाया। उन्होंने बस ऊपर की मंजिलें बना दीं, उन्हें बेच दिया और चले गए। अब, जिन लोगों ने यूनिट खरीदी है, वे इस समस्या से जूझ रहे हैं। एक अन्य निवासी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, 'हाल के दिनों में इमारत काफी झुक गई है। हमने पहले भी इसकी शिकायतें दर्ज कराई थीं। यहां पास में कई स्कूल हैं, जहां बच्चे सुबह-सुबह गुजरते हैं। हम भी इसी रास्ते से आते-जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह इमारत कब ढह जाए। आज इमारत और भी झुक गई है, इसका एंगल बिगड़ गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीजेपी ने किया स्वागत: रांका ने सरकार को याद दिलाए समझौते, कहा- युवाओं को न करें परेशान

नई दिल्ली। छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले को सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। आशुतोष रांका ने कहा, 'हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस देश में छात्रों और युवाओं को बिना किसी कारण के परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि 25 जुलाई को सरकार के साथ हुए हमारे समझौते का पालन किया जाएगा। क्या समझौता हुआ था? उन्होंने आगे कहा कि, 'समझौते के तहत, न केवल दिल्ली में बल्कि देश भर के सभी भाजपा शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों या छात्रों के खिलाफ कोई

कानूनी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हमें यह भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार आज की समय सीमा तक लिखित समझौता भेजेगी और इस अध्याय को समाप्त करने में मदद करेगी।' मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादती के आरोप प्रथम दृष्टया निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। अदालत ने कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच के लिए आगे चलकर स्वतंत्र समिति या विशेष जांच दल के गठन पर भी विचार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उन सभी राज्यों को निर्देश दिया, जहां प्रदर्शन हुए थे, कि सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए।

सम्पादकीय...

बचेगा जीवन

बदलते हुए समय में हम प्रकृति और पर्यावरण का महत्व तो समझ गए हैं लेकिन गंभीरता के साथ प्रकृति को संरक्षित करने के प्रयास नहीं कर रहे। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। खिलते हुए फूल, सुहानी हवा, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, ऊंचाई से गिरते झरने, बहता हुआ पानी, नदियां व पहाड़, सूरज, चांद और तारे, ये सब प्रकृति के ही अवयव हैं। संसार का अधिकांश साहित्य प्रकृति, प्रेम और सौन्दर्य को विषय बनाकर ही रचा गया है। प्रकृति हमें एक नया सौन्दर्यबोध प्रदान करती है। धरती को सौन्दर्य प्रदान करने में प्रकृति ने अतुलनीय योगदान दिया है। पेड़-पौधे, फूल-पत्तियां, झरने और पहाड़ धरती के आभूषण ही हैं। कल्पना कीजिए कि इन आभूषणों से रहित धरती हमें कैसी दिखाई देगी। यह हम सबका कर्तव्य है कि हम धरती के इन आभूषणों की चमक फीकी न पड़ने दें। हमें यह समझना होगा कि यह धरती सुन्दर रहेगी तो हमारा जीवन भी सुन्दर रहेगा। सवाल यह है कि हमसे प्यार करने और हमारे अन्दर प्रेम के बीज अंकुरित करने वाली प्रकृति से क्या हम प्यार करते हैं? शायद नहीं। तभी तो हम प्रकृति के प्रति पत्थर दिल हो गए हैं। कभी हम प्रकृति के विभिन्न अवयवों का क्षरण कर प्रदूषण बढ़ाते हैं, तो कभी जलवायु परिवर्तन के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हुए भी प्रकृति को कोसते हैं। यह दुखद है कि कभी धरती का बढ़ता हुआ तापमान प्रकृति को जख्म दे रहा है तो कभी हमारा व्यवहार प्रकृति के जख्मों को कुरेद रहा है। कुल मिलाकर हम उसी प्रकृति से बेवफाई कर रहे हैं जो हमें हमेशा वफा की सीख देती है। विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से यह बात सामने आती है कि प्रदूषण और धरती का तापमान बढ़ने के कारण सम्पूर्ण विश्व को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं में सूखा, बाढ़, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, अनेक जीव-जन्तुओं और पेड़-पौधों का विलुप्त होना आदि शामिल हैं। विचारणीय प्रश्न यह है कि जब हम इन प्राकृतिक समस्याओं से जूझने में व्यस्त होंगे तो प्यार के बारे में सोचने की फुर्सत किसे होगी? हालांकि प्राचीन समय में हमने प्रकृति से कई रिश्ते जोड़े। प्रकृति के विभिन्न अवयवों को हमने अपने परिवार की तरह माना। प्रकृति के इन अवयवों को हमने ईश्वर का दर्जा भी दिया। तभी तो हम आज तक धरती को धरती माता, तुलसी को तुलसी माता, गाय को गाय माता, सांप को नाग देवता, गंगा को गंगा मैया, चांद को चंदा मामा तथा सूरज को सूर्य देवता कह रहे हैं। क्यों न हम इस दौर में इसी शृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति से प्यार का एक नया रिश्ता जोड़ें। जैसे एक स्त्री मां, बहन, पत्नी और बेटी, किसी भी रूप में हमारे सामने हो सकती है, उसी तरह प्रकृति भी विभिन्न रूपों में हमारे सामने हो सकती है। प्रकृति मानसिक तनाव दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चिकित्सक भी मानसिक तनाव दूर करने के लिए हमें प्रकृति के बीच रहने की सलाह देते हैं। यह दुखद ही है कि प्रकृति जो शान्ति हमें प्रदान करना चाहती है, हम अपने व्यवहार से उस शान्ति को भंग कर देना चाहते हैं। मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण यह भी है कि इस दौर में हम लगातार प्रकृति से दूर होकर यांत्रिक होते जा रहे हैं। प्रकृति से दूर होना हमें भावनात्मक स्तर पर भी कमजोर कर रहा है। महानगरों में निवास करने वाले लोग तो कई-कई दिनों तक प्रकृति के दर्शन ही नहीं कर पाते। सुबह फ्लैट से बाहर निकलकर जाम में जूझते हुए कार्यालय पहुंचना तथा शाम को पुनः जाम से जूझते हुए घर पहुंचना उनकी नियति बन गई है। ऐसी स्थिति में शरीर के अन्दर पहुंची प्रदूषित वायु जीवन की लय बिगाड़ देती है। जीवन की इस लय को सुधारने के लिए हम प्रकृति के सान्निध्य में समय बिताना चाहते हैं। यह प्रकृति की उदारता और सहिष्णुता ही है कि वह उसे जख्म देने वाले इन्सान को अपना सान्निध्य देकर उस पर सब कुछ लुटा देना चाहती है। जब हम चारों तरफ से हार मान जाते हैं, तो प्रकृति ही हमें आशा की किरण दिखाकर एक नई ऊर्जा देती है। प्रकृति का स्नेहिल और शीतल स्पर्श हमें अवसाद के गहन अन्धकार से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। दरअसल हमने आज तक प्रकृति का ध्यान इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम प्रकृति से प्यार का रिश्ता नहीं जोड़ पाए। आज प्रकृति को बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन प्रकृति के जख्म बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके जरिए केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। यही कारण है कि आज प्रकृति को बचाने के लिए हल्ला तो मच रहा है लेकिन उससे प्यार का रिश्ता कायम नहीं हो पा रहा। हालांकि प्रकृति के विभिन्न अवयवों के साथ हमारा रिश्ता लगातार बना रहता है। प्रकृति स्वस्थ होगी तो हम भी स्वस्थ होंगे। तो आइए प्रकृति से अपने प्यार के रिश्ते को और मजबूत करें।

प्रकृति से दूर होना हमें भावनात्मक स्तर पर भी कमजोर कर रहा है। महानगरों में निवास करने वाले लोग तो कई-कई दिनों तक प्रकृति के दर्शन ही नहीं कर पाते। सुबह फ्लैट से बाहर निकलकर जाम से जूझते हुए कार्यालय पहुंचना तथा शाम को पुनः जाम से जूझते हुए घर पहुंचना उनकी नियति बन गई है। ऐसी स्थिति में शरीर के अन्दर पहुंची प्रदूषित वायु जीवन की लय बिगाड़ देती है। जीवन की इस लय को सुधारने के लिए हम प्रकृति के सान्निध्य में समय बिताना चाहते हैं। यह प्रकृति की उदारता और सहिष्णुता ही है कि वह उसे जख्म देने वाले इन्सान को अपना सान्निध्य देकर उस पर सब कुछ लुटा देना चाहती है। जब हम चारों तरफ से हार मान जाते हैं, तो प्रकृति ही हमें आशा की किरण दिखाकर एक नई ऊर्जा देती है। प्रकृति का स्नेहिल और शीतल स्पर्श हमें अवसाद के गहन अन्धकार से बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। दरअसल हमने आज तक प्रकृति का ध्यान इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम प्रकृति से प्यार का रिश्ता नहीं जोड़ पाए। आज प्रकृति को बचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन प्रकृति के जख्म बढ़ते ही जा रहे हैं।

'छात्र आंदोलन' : इसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता

मई में अपनी शुरुआत के बाद से, कॉकरोच जनता पार्टी (सी.जे.पी.) एक महत्वपूर्ण आंदोलन में विकसित हो गई है, जिसने कई व्यक्तियों और विभिन्न विपक्षी समूहों का ध्यान आकर्षित किया है। यह भारत के युवाओं के बीच असंतोष की एक शक्तिशाली आवाज बन गई है, जो विभिन्न मुद्दों पर सरकार को चुनौती दे रही है। सी.जे.पी. ने गति पकड़ी है और कई लोगों को प्रेरित किया है, जो भारतीय राजनीति में इसके महत्व को उजागर करता है। यह भारत में सबसे प्रमुख युवा आंदोलनों में से एक के रूप में खड़ा है, जो सरकार के खिलाफ सार्वजनिक विरोध का प्रतिनिधित्व करता है। 'कॉकरोच' विरोध प्रदर्शन मेडिकल कॉलेजों और सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के विवादास्पद दावों के जवाब में शुरू किया गया था। शुरुआत में इन विशिष्ट परीक्षाओं पर केंद्रित, यह जल्द ही एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। अब, इसमें न केवल सीधे प्रभावित छात्र, बल्कि पेशेवर, माता-पिता और आम नागरिक भी शामिल हैं, जो देश में आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को लेकर निराशा जाहिर करते हैं। आंदोलन का नाम भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई एक टिप्पणी से उपजा है, जिन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। सी.जे.पी. ने इस अपमान को लिया और इसे युवाओं के लिए, एक ललकार में बदल दिया। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए और खुद को 'मानद कॉकरोच' बताया। उन्होंने नई दिल्ली में शांतिपूर्ण जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 दिन तक भूख हड़ताल भी की। अपने अस्पताल के बिस्तर से एक वीडियो में, उन्होंने कहा कि उन्हें लिखित आश्वासन मिला है कि सरकार परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करेगी और विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, साथ ही भविष्य में लीक को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर था। उन्होंने इन मुद्दों से प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजे की भी मांग की, जो वास्तविक बदलाव के लिए उनकी इच्छा को उजागर करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि परीक्षा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों से निपटने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी, जो विवाद पर उनकी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जोर दिया कि युवाओं का कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सी.जे.पी. की स्थापना अभिजीत दीपके ने की, जो बेरोजगार युवाओं के बारे में मुख्य न्यायाधीश की अपमानजनक टिप्पणियों को सुनने के बाद कार्य करने के लिए प्रेरित हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में सवाल किया, ''क्या होगा अगर सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं?'' जैसे-जैसे परीक्षा लीक के और आरोप सामने आए, सार्वजनिक विरोध तेज होता गया। ये परीक्षाएं भारत में नौकरी के अवसरों और सामाजिक गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनकी अखंडता के लिए कोई भी खतरा उन छात्रों हेतु महत्वपूर्ण देरी और तनाव का कारण बन सकता है, जो कीमती अध्ययन समय खोने से डरते हैं। सी.जे.पी. अलग दिखती है क्योंकि यह पारंपरिक राजनीतिक दलों से संबद्ध नहीं है, जो जमीनी प्रयासों में विश्वास और गर्व को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह स्वतंत्रता लोगों को उम्मीद देती है कि युवा व्यक्ति सोशल मीडिया और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से सार्थक बदलाव ला सकते हैं। यह आंदोलन जून में तब चर्चा में आया, जब दीपके अमेरिका से लौटे और विभिन्न शहरों और विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें सैकड़ों समर्थक इकट्ठे हुए और राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। जो ऑनलाइन व्यंग्य के रूप में शुरू हुआ, वह युवा निराशा की एक मजबूत अभिव्यक्ति में बदल गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, सार्वजनिक आक्रोश बढ़ गया। राजनीतिक विरोधियों ने संसदीय सत्रों के दौरान आंदोलनकारियों की मांगों को दोहराया है। कुछ बॉलीवुड हस्तियां, जिन्हें इन विरोध प्रदर्शनों पर चुप रहने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था, ने छात्रों की सामूहिक कार्रवाई के समर्थन में बात की, सरकार की सीधे आलोचना किए बिना उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। इनमें आमिर खान, प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान शामिल हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शनों को संबोधित नहीं किया लेकिन परीक्षा लीक मुद्दे पर उनकी स्वीकृति से पता चलता है कि वह चिंताओं से अवगत हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि मोदी दबाव में दिख रहे थे और उनके लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें उनके शिक्षा मंत्री को हटाना भी शामिल है। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका सहित विपक्षी नेताओं ने मोदी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि उनकी पार्टी ने वीडियो में साझा किया। ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे अन्य नेता भी सरकार के आलोचक थे। चरमोत्कर्ष तब आया, जब प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया। सी.जे.पी. चिल्ला रहा था, ''हम जीत गए हैं।''

जंतर-मंतर पर उनकी भीड़ जल्दी ही तितर-बितर हो गई। क्या यह गलत समय पर सही कार्रवाई है? भारत के मुख्य न्यायाधीश (सी.जे.आई.) का किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है और न ही उनकी कोई विशिष्ट विचारधारा है। यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त शुरू हुआ, जो एक प्रमुख सार्वजनिक मुद्दे को संबोधित करता है, जो सरकार के लिए एक चुनौती पेश करता है। उन्हें इसे सावधानीपूर्वक संभालने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ भाजपा सदस्य भी 'नीट' को लेकर चिंतित हैं। हमें यह देखने की जरूरत है कि आने वाले महीनों में यह स्थिति कैसे विकसित होती है।

जनपद प्रतापगढ़ में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों का स्वर्णिम भविष्य गढ़ रही "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना"

प्रदेश में अनाथ, निराश्रित और आर्थिक संकट का सामना कर रहे बच्चों को सामाजिक सुरक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' का संवेदनशील एवं प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल है, जो माता-पिता अथवा किसी एक अभिभावक को खो चुके बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसाधनों एवं आर्थिक अभाव के कारण किसी भी बच्चे की शिक्षा बीच में न छूटे और उनका भविष्य सुरक्षित तथा आत्मनिर्भर बन सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस दूरदर्शी योजना के अंतर्गत मार्च-2020 के बाद जिन बच्चों के माता, पिता अथवा दोनों का असमय निधन हो गया है, उन्हें शिक्षा, पोषण और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि बच्चों के 23 वर्ष की आयु तक अथवा शिक्षा ग्रहण करने की अवधि तक सीधे लाभार्थी या उनके विधिक अभिभावक के बैंक खाते में पारदर्शी प्रक्रिया (डीबीटी) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। योजना के तहत बच्चों के सर्वांगीण विकास और शैक्षणिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले पात्र छात्र-छात्राओं को डिजिटल माध्यमों से अपनी पढ़ाई सुचारू रखने हेतु निःशुल्क टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त निराश्रित बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य हेतु विवाह योग्य आयु होने पर आर्थिक सहायता का विशेष प्रावधान किया गया है तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच व परामर्श की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में जनपदों में योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर आवेदन प्रक्रिया को अत्यंत सरल और सुलभ बनाया गया है ताकि प्रभावित परिवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पारदर्शी चिन्हिकरण और सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक पात्र बच्चे तक योजना का लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में जनपद प्रतापगढ़ में भी महिला कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से योजना का बेहद सफल और प्रभावी क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। जनपद में वित्तीय वर्ष 2026-27 के जून माह तक 471 नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। वर्तमान समय में प्रतापगढ़ जनपद के कुल 2,907 बच्चे इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के इस सफल क्रियान्वयन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण जनपद प्रतापगढ़ के टाउनगंज की निवासी और कक्षा-8 की होनहार छात्रा दर्पिता सिंह है। दर्पिता के पिता स्वर्गीय प्रदीप सिंह के आकस्मिक और असमय निधन के बाद परिवार पर आर्थिक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार की दयनीय स्थिति के कारण दर्पिता की माता प्रतिभा वर्मा के सामने बेटी की पढ़ाई जारी रखने और उसके भविष्य को लेकर गहरी चिंता पैदा हो गई थी। सीमित संसाधनों और आर्थिक संकट के कारण ऐसा लगने लगा था कि दर्पिता की शिक्षा बीच में ही थम जाएगी।

स्क्रीन का प्यार / रिस्क हजार

आज के डिजिटल युग में स्क्रीन हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि ने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इनके प्रति बढ़ता लगाव कई गंभीर जोखिम भी साथ लेकर आया है। मनोरंजन, शिक्षा और संवाद के लिए उपयोगी यह तकनीक धीरे-धीरे हमारी जीवनशैली को प्रभावित कर रही है। आज के युवा डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। उनकी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है और रात सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग पर समाप्त होती है। स्मार्टफोन ने ज्ञान, मनोरंजन और अवसरों के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इसके प्रति बढ़ता आकर्षण अनेक जोखिम भी साथ लेकर आया है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम स्क्रीन का उपयोग कर रहे हैं या स्क्रीन हमें उपयोग कर रही है? इंटरनेट और सोशल मीडिया ने युवाओं को दुनिया से जोड़ा है, लेकिन इससे एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा भी जन्मी है। लाइक्स, फॉलोअर्स और वर्चुअल पहचान की दौड़ ने आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया है। कहते है प्यार अंधा होता है, लेकिन आजकल का प्यार अंधा होने के साथ-साथ थोड़ा अंगूठा प्रधान भी हो गया है। वह दौर गया जब दिल और जिस्म की बात जुबान पर आते-आते रुक जाती थी।

आज चाहे भावनाओं का इजहार हो या शारीरिक इच्छाओं का सब कुछ जुबान तक आने से पहले सीधे अंगूठे से होते हुए व्हॉट्सएप की स्क्रीन पर टाइप हो जाता है। चौंकिए मत यह कोई फिल्मी जुमला नहीं, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद दर्जनों मनोवैज्ञानिक रिसर्च और समाजशास्त्रीय अध्ययनों का कड़वा या कहें कि मीठा सच है। सामान्यतया यह माना जाता है कि कपल्स जब बेड पर साथ होते हैं, तब उनके बीच प्यार और शारीरिक आकर्षण का इजहार पूरे परवान पर होगा लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। आज के दौर के कपल्स बिस्तर पर एक- दूसरे के बगल में लेटे हुए जितने इमोशनली और फिजिकली ब्लैंक महसूस करते हैं, फोन की स्क्रीन पर वे उतने ही बड़े शायर और बोल्ड रोमियो बन जाते हैं। जो बातें या जो फैंटेसीज वे एक-दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बेड पर नहीं कह पाते, उन्हें वे इमोजी और हॉट मैसेजेस के सहारे बड़े धड़ल्ले से लिख भेजते हैं। दरअसल जब आप आमने-सामने होते हैं, तो जो मुंह से निकल गया, सो निकल गया। उसे आप डिलीट या एडिट नहीं कर सकते। बेड पर रोमांटिक या हॉट होने के चक्कर में कई बार मुंह से कोई ऐसी अजीब बात निकल जाती है कि पूरे मूड का ही बंटाधार हो जाता है। इसके उलट, जब आप टेक्स्ट के रूप में अपनी फीलिंग्स या डिजायर्स का इजहार कर रहे होते हैं, तो आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। आप एक लाइन लिखते हैं, फिर सोचते हैं, आप उसे मिटाते हैं, एक । इमोजी जोड़ते हैं, थोड़ा और हॉट शब्द ढूंढते हैं और फिर सेंड करते हैं। यानी आप अपनी कामुकता और प्यार का बेस्ट, सबसे पॉलिश्ड वर्जन सामने वाले को परोसते हैं।

यह सुविधा बिस्तर पर उपलब्ध नहीं होती। वहां तो जो है, सो ऑन-एयर लाइव है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि बेडरूम की असली गर्माहट पर स्मार्टफोन की डिजिटल स्क्रीन भारी पड़ रही है? आइए, विज्ञान और रोजमर्रा के जीवन के नजरिए से इस डिजिटल लव लाइफ का पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान में एक बेहद मशहूर टर्म है- Online Disinhibition Effect. आसान भाषा में कहें तो, जब हमारे और सामने वाले के बीच एक कांच की स्क्रीन आ जाती है, तो हमारे अंदर की झिझक, डर, शर्म और लोक-लाज अचानक गायब हो जाती है। डिजिटल स्क्रीन इंसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। बिस्तर पर जब दो लोग साथ होते हैं, तो वहां आई कॉन्टैक्ट और शारीरिक मौजूदगी होती है।

सामने वाले के चेहरे के हाव-भाव, उसकी सांसें एक तरह का अदृश्य दबाव बनाती हैं। हमें डर होता है कि अगर हमने अपने दिल की कोई गहरी बात कही या अपनी कोई शारीरिक इच्छा जताई, तो पार्टनर का तुरंत रिएक्शन क्या होगा? कहीं वह हमें जज न करने लगे? कहीं वह रिजेक्ट न कर दे? लेकिन फोन पर आपके पास एक अदृश्य ढाल होती है। इस विषय पर जर्नल ऑफ कंप्यूटर-मीडिएटेड में छपी एक रिसर्च साफ बताती है कि टेक्सटिंग या सेक्सटिंग कपल्स को अपनी असुरक्षा को छिपाने में मदद करती है। जो बातें वे बेड पर आमने-सामने बैठकर नहीं बोल पाते, उन्हें वे स्क्रीन के पीछे छिपकर आसानी से लिख देते हैं। जब हम प्यार के इजहार की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ आई लव यू शामिल नहीं होता, बल्कि शारीरिक स्तर पर एक-दूसरे को चाहना भी शामिल है। आज के कपल्स फिजिकल लव के एक्सप्रेशन में बेड से कहीं ज्यादा माहिर है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक प्रसिद्ध स्टडी के अनुसार, लगभग 32% वयस्क मानते हैं कि वे अपने पार्टनर के साथ नियमित रूप से सेक्सटिंग करते हैं। रिसर्च के मुताबिक, सेक्सटिंग कपल्स के लिए एक डिजिटल फोरप्ले की तरह काम करती है। कई लोग स्वभाव से शर्मीले होते हैं। वे अपनी वाइल्ड फैंटेसीज, अपनी पसंद या नापसंद को खुलकर नहीं बता पाते उन्हें लगता है कि सीधे मुंह ऐसी बातें बोलना उनके पार्टनर को अजीब लग सकता है। लेकिन टेक्स्ट मैसेज पर वे अचानक बोल्ड हो जाते हैं। फोन पर वे अपनी हर दबी हुई शारीरिक इच्छा को बिना किसी हिचक के शब्दों में पिरो देते हैं। यह जो टेक्स्ट पर फिजिकल लव का खुलकर इजहार है, वह बेडरूम की पारंपरिक झिझक को तोड़ देता है। लोग स्क्रीन पर जितने सेक्सुअली एक्सप्रेसिव है, बेड पर लाइट ऑफ होते ही उतने ही पारंपरिक या शांत हो जाते हैं। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक दूसरे पर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए सेक्सटिंग करते है, भले ही सामने आने पर उनकी बत्ती गुल क्यों न हो जाए जो लोग सीधे मुंह दो सीधे शब्द नहीं बोल पाते, वे टेक्स्ट पर कामदेव बन जाते हैं।

इसके पीछे काम करता है प्रसिद्ध समाजशास्त्री वाल्थर द्वारा दिया गया हाइपरपर्सनल मॉडल। यह थ्योरी बताती है कि टेक्स्ट या डिजिटल मीडिया पर हम खुद को ज्यादा बेहतर, आकर्षक, सिडक्टिव और परफेक्ट तरीके से पेश कर सकते हैं। इस डिजिटल रोमांस पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने एक बेहद दिलचस्प स्टडी की है। मशहूर शोधकर्ता जेफ्री हैनकॉक के अनुसार, डिजिटल मीडिया पर मैसेज भेजते वक्त लोग अक्सर आमने-सामने की तुलना में अधिक गहरी और हाइपर पर्सनल बातचीत करते हैं। इसका कारण यह है कि लिखते समय हमारे पास सोचने समझने और सही शब्दों को चुनने का पर्याप्त समय होता है जिसे रिफ्लेक्शन टाइम कहते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए अक्सर कपल्स के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। दिनभर के काम की थकान, ऑफिस का स्ट्रेस और घरेलू चिंताएं दिमाग में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बज रही होती है। ऐसे में फिजिकल होने का मूड बनाना भी एक भारी काम लगने लगता है। लेकिन फोन की दुनिया रंग-बिरंगी है। वहां अगर आपके पास शब्द नहीं भी है, तो भी आपके पास हॉट जीआईएफ, डर्टी टॉक्स विडियोज और इमोजी की पूरी बारात है। कपल्स या लवर्स को लगता है कि टेक्स्ट पर हम विजुअल्स को इस्तेमाल करके वे अपने बीच की शारीरिक और मानसिक दूरी को ज्यादा मसालेदार तरीके से पाट पाते है। एक और कड़वा सच यह है कि बेडरूम में कपल्स के ऊपर बॉडी इमेज और परफॉर्मेंस का एक अनकहा शारीरिक दबाव होता है। पेट थोड़ा बाहर निकला है, बाल बिखरे हुए है, चेहरे पर थकान है या स्ट्रेस के कारण मूड नहीं बन रहा, ये सब चीजें इंसान को अपने ही शरीर को लेकर कॉन्सस कर देती है। जब आप खुद को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो आप बेड पर खुलकर न तो प्यार जता पाते हैं और न ही शारीरिक रूप से पूरी तरह इन्वॉल्व हो पाते हैं। दूसरी ओर, जब आप ऑफिस की कैब में बैठे हो, या घर के किसी दूसरे कोने में हो। तब आप कैसे दिख रहे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब्जी के दाग लगे टी शर्ट पहने हुए भी दुनिया के सबसे सिडक्टिव और रोमांटिक इंसान की तरह टेक्स्ट टाइप कर सकते है। वहां सिर्फ आपकी कल्पनाएं और भावनाएं यात्रा करती है, आपका असल शरीर नहीं। इसलिए शरीर के बंधनों और कमियों से मुक्त होकर कल्पनाओं का वो अंगूठा ज्यादा बेहतर तरीके से फिजिकल लव एक्सप्रेस कर पाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस डिजिटल परफेक्शन के चक्कर में कहीं हम अपनी असल दुनिया की शारीरिक और मानसिक अंतरंगता को खो तो नहीं रहे? मैसेज पर इंटरनेट के वाइल्ड लवर बन जाना और बेड पर आते ही स्मार्टफोन की स्क्रीन स्क्रॉल करने लगना, यह आधुनिक रिश्तों की एक बड़ी विडंबना बन चुका है। स्क्रीन पर होने वाली सेक्सटिंग और प्यार बेशक खूबसूरत, रोमांचक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, लेकिन जब तक वह बोल्डनेस फोन से बाहर निकलकर बेड पर एक-दूसरे को छूने, आंखों में देखने और असल जिंदगी में बिना झिझक के अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं बदलेगी, तब तक रिश्ता सिर्फ एक डिजिटल भ्रम ही रहेगा। इसलिए 'स्क्रीन से प्यार' कीजिए, लेकिन 'रिस्क हजार' को समझते हुए संतुलित डिजिटल जीवन अपनाइए।

प्रदेश में स्थापित ऊर्जा वन हरित भविष्य, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस पहल

वर्तमान समय में पूरी दुनिया ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत जैसे विशाल ग्रामीण आबादी वाले देश में आज भी बड़ी संख्या में परिवार भोजन पकाने और घरेलू आवश्यकताओं के लिए जलौनी लकड़ी पर निर्भर हैं। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक वनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे वनों का क्षरण, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव तथा पर्यावरणीय असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत ऊर्जा वन स्थापित करने की अभिनव पहल की है। यह पहल केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी प्रयास है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में ऊर्जा वन स्थापित कर सरकार ने भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय संतुलन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है।

ऊर्जा संकट और जलौनी लकड़ी की चुनौती

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में परिवार ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं। विशेषकर वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की दैनिक आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा जलौनी लकड़ी पर आधारित है। लगातार बढ़ती मांग के कारण प्राकृतिक वनों से लकड़ी का दोहन बढ़ता है, जिससे वन संपदा पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वनों के निकट रहने वाले ग्रामीण अक्सर जलौनी लकड़ी का उपयोग करते हैं। देश में वन क्षेत्रों के आसपास करोड़ों ग्रामीण निवास करते हैं। जलौनी लकड़ी की मांग अत्यंत व्यापक है और यदि इसका वैकल्पिक एवं नियोजित समाधान विकसित नहीं किया गया, तो भविष्य में प्राकृतिक वनों पर दबाव और अधिक बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में ऊर्जा वनों की अवधारणा एक व्यावहारिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान के रूप में प्रदेश सरकार ने ठोस कदम उठाए है।

ऊर्जा वन की अवधारणा

ऊर्जा वन ऐसे विशेष वृक्षारोपण क्षेत्र है, जहां तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजातियों का रोपण किया जाता है ताकि अपेक्षाकृत कम समय में पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध हो सके। इन वनों का उद्देश्य प्राकृतिक वनों पर निर्भरता कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जलौनी लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 जुलाई 2026 को आयोजित 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक हेक्टेयर क्षेत्र में ऊर्जा वन स्थापित किए। इस पहल का उद्देश्य भविष्य में जलौनी लकड़ी की आवश्यकता को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना तथा प्राकृतिक वनों को अनावश्यक दोहन से बचाना है।

तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजातियों का चयन

ऊर्जा वनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें ऐसी प्रजातियों का चयन किया जाए जो कम समय में तेजी से विकसित हों तथा पर्याप्त मात्रा में बायोमास उपलब्ध करा सकें। इसी उद्देश्य से ऊर्जा वनों में सिरस, बबूल, सुबबूल, यूटेल तथा कदम्ब जैसी तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रजातियों का रोपण किया गया। इन वृक्षों की विशेषता यह है कि ये अपेक्षाकृत कम समय में विकसित होकर पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही ये विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं भूमि परिस्थितियों में भी अच्छी वृद्धि करते हैं। इन प्रजातियों से प्राप्त लकड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में उपयोगी होने के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से भी लाभकारी है।

प्रदेशव्यापी अभियान

ऊर्जा वन स्थापना का अभियान प्रदेश के सभी विकास खण्डों में एक साथ संचालित किया गया। प्रत्येक विकास खण्ड में न्यूनतम एक हेक्टेयर भूमि पर ऊर्जा वन विकसित किए गए, जिससे यह अभियान पूरे प्रदेश में समान रूप से लागू हो सका। इस महाअभियान के अंतर्गत 242.40200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2,81,233 पौधों का रोपण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ते हुए एक व्यापक और योजनाबद्ध कार्यक्रम लागू किया है।

प्राकृतिक वनों पर दबाव होगा कम

ऊर्जा वनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे प्राकृतिक वनों से जलौनी लकड़ी की कटाई की आवश्यकता कम होगी। जब ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से विकसित ऊर्जा वनों से ईंधन उपलब्ध होगा, तब प्राकृतिक वन अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित रह सकेंगे। इससे वनों में रहने वाले वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहेगा, जैव विविधता का संरक्षण होगा तथा वनों की पारिस्थितिकी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक वन केवल लकड़ी का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे जल संरक्षण, वर्षा चक्र, मिट्टी संरक्षण तथा जलवायु संतुलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा वन इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध होंगे।

कार्बन अवशोषण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला

ऊर्जा वन केवल ईंधन की आवश्यकता पूरी करने तक सीमित नहीं है। यदि भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का व्यापक विस्तार हो जाता है और जलौनी लकड़ी की मांग कम भी हो जाती है, तब भी इन ऊर्जा वनों का महत्व बना रहेगा। वृक्ष अपने जीवनकाल में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर उसे जैविक पदार्थ के रूप में संग्रहित करते हैं। इसे कार्बन अवशोषण (ब्ंतइवद `मुनमेजतंजपवद) कहा जाता है। बड़ी संख्या में लगाए गए वृक्ष वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा कम करने में सहायक होंगे, जिससे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार ऊर्जा वन भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ग्रामीण विकास को मिलेगा बल

ऊर्जा वनों से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे। स्थानीय स्तर पर जलौनी लकड़ी की उपलब्धता बढ़ने से ग्रामीण परिवारों का समय और श्रम बचेगा। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को दूर-दराज के क्षेत्रों से लकड़ी लाने की आवश्यकता कम होगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में ऊर्जा वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन से ग्रामीण समुदायों को रोजगार, पौध संरक्षण, रखरखाव तथा वृक्ष आधारित आजीविका के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस अभियान को सफल बनाने में ग्राम्य विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग ने भी सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता प्रदान की। ग्राम पंचायतों, विकास खण्डों तथा स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों से उपयुक्त भूमि का चयन, पौधरोपण तथा अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो सका। विभिन्न विभागों की यह सहभागिता सुशासन और समन्वित विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है।

भविष्य की दिशा

ऊर्जा वन की यह पहल सतत विकास की अवधारणा को साकार करती है। यह कार्यक्रम ऊर्जा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास और जलवायु संरक्षण जैसे अनेक लक्ष्यों को एक साथ संबोधित करता है। भविष्य में यदि इन ऊर्जा वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए, नियमित निगरानी की जाए तथा स्थानीय समुदायों को इनके संरक्षण से जोड़ा जाए, तो यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकता है। 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में स्थापित ऊर्जा वन ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक दूरदर्शी एवं प्रभावी पहल है। 242.40200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2,81,233 पौधों का रोपण कर प्रदेश ने यह संदेश दिया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने बन्ना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सत्य पैलेस्टाईन एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2013/48883)

34 लाख की लागत से बनी दो सीसी सड़कों का विधायक पी.एन. पाठक ने किया लोकार्पण

कसया/कुशीनगर। कुशीनगर के विधायक पी.एन. पाठक ने मंगलवार को विधायक निधि से निर्मित दो सीसी सड़कों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकार्पण किया। दोनों परियोजनाओं पर लगभग 34 लाख रुपये की लागत आई है। विधायक ने बैजनाथपुर में लगभग 19 लाख रुपये तथा रामबर में करीब 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित सीसी सड़कों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। लोकार्पण के बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता है। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र का कोई भी गांव विकास से वंचित न रहे। कार्यक्रम में भाजपा नेता रूपेश तिवारी, जेई पी.एन. मिश्रा, मुन्ना लाल श्रीवास्तव, शेर सिंह, राज पाठक, राजन सिंह, चंदगी मल्ल, अनिल सिंह, सूर्यनाथ यादव, राकेश यादव, अमरजीत कुशवाहा, आद्या पांडेय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

हादसे में घायल पिता-पुत्र की मदद को रुके विधायक, अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल

पटहेरवा/कुशीनगर।

फाजिलनगर क्षेत्र के निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास मंगलवार को सड़क हादसे में घायल पिता-पुत्र की मदद कर कुशीनगर विधायक पी.एन. पाठक ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। उन्होंने काफिला रुकवाकर दोनों घायलों को अपनी कार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) फाजिलनगर पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। जानकारी के अनुसार, रजवटिया निवासी प्रेमशंकर सिंह (55) और उनके पुत्र अजित सिंह (27) बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। उसी समय वहां से गुजर रहे विधायक की नजर घायलों पर पड़ी। उन्होंने तत्काल वाहन रुकवाया और सहयोगियों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। समय पर उपचार मिलने से घायलों को शीघ्र चिकित्सकीय सहायता मिल सकी। घटना के दौरान विधायक के साथ उनके सहयोगी भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के समय दिखाई गई इस तत्परता की सराहना की।

भारतीय उद्योग व्यापार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष बने संतोष जायसवाल, व्यापारियों ने किया भव्य स्वागत

कुशीनगर। भारतीय उद्योग व्यापार परिषद न्यास भारत की बैठक रविवार को नगर स्थित शिवराम होटल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अशोक टिबड़ेवाल ने तथा संचालन संजय शर्मा ने किया। बैठक में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गोयल ने संतोष जायसवाल को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करने की घोषणा की। घोषणा होते ही उपस्थित व्यापारियों ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही नगर इकाई के गठन की जिम्मेदारी विनय जायसवाल को सौंपते हुए उन्हें नगर संयोजक बनाया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए परिषद हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार अग्रवाल, राजेश तुलस्यान और अखिलेश गोयल ने डॉ. सुरेश चंद्र गुप्ता तथा अध्यक्षता कर रहे अशोक टिबड़ेवाल का माल्यार्पण कर सम्मान किया। डॉ. गुप्ता ने भी व्यापारियों को संबोधित किया। बैठक के दौरान व्यापारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गोयल एवं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संतोष जायसवाल को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जिले और नगर के बड़ी संख्या में व्यापारी एवं परिषद पदाधिकारी उपस्थित रहे।

मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दबंगों का तांडव, घर में तोड़फोड़

गोरखपुर।

खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज बाजार की रहने वाली कु. सोनम पुत्री राजमन ने गोरखपुर जर्नलिस्ट्स प्रेस क्लब सभागार में प्रेस वार्ता कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी विपक्षी दबंगों द्वारा लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके घर में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। प्रार्थिनी ने बताया कि दिनांक 23 जुलाई 2026 को उनके सगे चाचा द्वारा अभियुक्तगणों के खिलाफ थाना खोराबार में मु.अ.सं. 0031/2026 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी दौरान जब उनके माता-पिता बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके पिता का पैर तोड़ दिया गया, जबकि माता को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रार्थिनी और उसकी दोनों बहनों के साथ अभद्रता करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए गए और मारपीट की गई। घटना की सूचना 112 नंबर पर देने के बाद

पुलिस मौके पर पहुंची और 102 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को एम्स कुड़ाघाट में भर्ती कराया गया। उन्होंने आगे बताया कि इलाज के बाद जब 27 जुलाई 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे वे अपने चाचा रणजीत के साथ घर लौटीं, तो देखा कि उपजिलाधिकारी के आदेश पर 10 जुलाई 2026 को राजस्व टीम द्वारा कराया गया जमीन का सीमांकन विपक्षियों ने उखाड़कर फेंक दिया है। साथ ही उनकी दीवार और टीनशेड को गिराकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया

पीड़िता ने प्रेस वार्ता में सुनाई आपबीती, जान-माल की सुरक्षा की लगाई गुहार

कि विपक्षीगण लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरे परिवार में भय का माहौल है। उन्होंने आशंका जताई कि आरोपी कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से कु. सोनम ने प्रशासन से मांग की है कि राजस्व टीम द्वारा किए गए सीमांकन को पुनः स्थापित कराया जाए तथा पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में उखाड़े गए पत्थरों को दोबारा लगवाया जाए। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। कुमारी सोनम ने प्रशासन से अपील की कि थानाध्यक्ष खोराबार को निर्देशित कर आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई की जाए और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज में संस्थापक पंडित मातादीन शर्मा जी की जयंती समारोह की तैयारियां शुरू

पडरौना, कुशीनगर। हनुमान इंटरमीडिएट कॉलेज, पडरौना के संस्थापक, पूर्वांचल के गौरव, संस्कृति एवं संस्कृत के अनन्य उपासक पूज्य पंडित मातादीन शर्मा जी की 96वीं जयंती एवं विद्यालय के वार्षिकोत्सव के आयोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। यह समारोह 8 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। समारोह की तैयारियों के क्रम में विद्यालय परिसर में आज से खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। कबड्डी प्रतियोगिता के बालक वर्ग का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला प्रचारक अभय जी ने किया, जबकि बालिका वर्ग का शुभारंभ रियल पैराडाइज एकेडमी की प्रधानाचार्या डा. सुनीता पांडेय के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेन्द्र दत्त शुक्ल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि संस्थापक पंडित मातादीन शर्मा जी के आदर्श, अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण आज भी विद्यालय

परिवार के लिए प्रेरणास्रोत हैं। विद्यालय के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रतियोगिताओं में जूनियर बालिका वर्ग के रोमांचक मुकाबले में कक्षा 7 की टीम ने कक्षा 6 को पराजित किया। वहीं बालक वर्ग में कक्षा 9 (अ) ने कक्षा 9 (ब) को हराकर अगले चरण में प्रवेश किया। विद्यालय में विभिन्न खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का क्रम आगामी दिनों तक जारी रहेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के विवेक शर्मा सारस्वत, सचिन मधेशिया, उमेश प्रसाद, वंदना सिंह, अनुराधा शुक्ला, मिथिलेश कुशवाहा, मिथिलेश उपाध्याय, अवधेश गौड़, विजय पांडेय तथा अवधेश कुशवाहा का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता में रिजवान अंसारी ने रेफरी तथा राज ने स्कोरर की भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

आईजीआरएस में फर्जी निस्तारण पर कड़ा रुख : डीएम ने 5 अफसरों को थमाया नोटिस

देवरिया। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर मिलने वाली शिकायतों का धरातल पर समाधान करने के बजाय खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों पर कलेक्ट्रेट प्रशासन ने चाबुक चलाया है। शिकायतों के त्रुटिपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना निस्तारण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार को जिले के पांच प्रशासनिक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में हिदायत दी है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा और फरियादियों से लिए गए सीधा फीडबैक के दौरान यह बड़ी प्रशासनिक चूक उजागर हुई। समीक्षा में पाया गया कि पीएम/सीएम आवास योजना, सड़क मरम्मत, नाली निर्माण और जर्जर रास्तों के निर्माण से जुड़ी

जनसमस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना ही रिपोर्ट लगा दी गई थी, जिससे शिकायतकर्ता असंतुष्ट थे। इस लापरवाही पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी पथरदेवा, खंड विकास अधिकारी भलुअनी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सलेमपुर, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भाटपाररानी तथा

आवास, सड़क और नाली की शिकायतों पर कागजी निस्तारण पड़ा भारी

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) बरहज से स्पष्टीकरण तलब किया है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार से समस्त विभागीय अधिकारियों को कड़ा संदेश जारी करते हुए कहा कि जनसमस्याओं का पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। शिकायतों का केवल निस्तारण दिखाना मंशा नहीं है, बल्कि पीड़ित को मौके पर न्याय मिलना अनिवार्य है। उन्होंने ताकीद की कि भविष्य में भी यदि समीक्षा या फीडबैक के दौरान फर्जी अथवा त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट लगाने की बात सामने आई तो संबंधित अफसर की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को गोरखपुर पहुंच गए। गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री शाम को सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी के परिचय एवं सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे पदाधिकारियों से संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है। वे विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे तथा परंपरानुसार धार्मिक अनुष्ठानों में भी शामिल होंगे।

नोएडा-गाजियाबाद समेत दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, कई इलाकों में जलभराव

नई दिल्ली। दिल्ली और इसके आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मंगलवार सुबह कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली और मौसम खुशनुमा हो गया। नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव और लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा।

सदर बाजार समेत कई इलाकों में जलभराव

जानकारी के अनुसार, मंगलवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बारिश की बूंदों ने दस्तक दी। इससे पहले, सोमवार दोपहर में भी कुछ इलाकों में बारिश हुई थी और रात के समय भी बूंदाबांदी देखी गई थी। इन बारिशों के कारण हवा में नमी बढ़ी और तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को उमस से बड़ी राहत मिली। दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम में बारिश हो रही है। दिल्ली के सदर बाजार समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया। दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। मंगलवार दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली के जनपथ रोड, शंकर विहार क्षेत्र सहित कई निचले इलाके जलमग्न हो गए, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग-8 (एनएच 8) पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया।

पंडित पंत मार्ग पर भारी जलभराव

नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर तेज बारिश के बाद सड़क पर भारी जलभराव हो गया है। जलभराव के कारण वाहन धीमी गति से गुजर रहे हैं और लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

करोड़ खर्च पर फिर पानी में डूबा ग्रेनो का औद्योगिक सेक्टर इकोटेक तीन

तेज बारिश ने एक बार फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खोल दी है। औद्योगिक सेक्टर इकोटेक तीन मंगलवार की बारिश में फिर डूब गया है। सड़कों पर दो से तीन फीट पानी भर गया है। कई जगह उद्योगों में भी पानी भर गया। जबकि यातायात भी प्रभावित है। वाहन वैकल्पिक रास्ते खोजते नजर आए। कुछ ने पानी से निकलने की कोशिश की तो वाहन खराब हो गए। उद्यमियों का कहना है कि प्राधिकरण ने करोड़ खर्च कर पानी निकासी के लिए नाला बनाया। 9 जुलाई की बारिश के बाद कई दिन तक नालियों को साफ किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। पानी भरने से उद्यमी व कर्मचारी उद्योगों से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं ग्रेनो में अन्य जगह भी जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आईएमडी के मुताबिक, सोमवार शाम 5 बजकर 50 मिनट तक सफदरजंग में आठ मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश रिज इलाके में 19.4 मिमी दर्ज की गई।

इसके बाद लोधी रोड पर 11.5 मिमी रिकॉर्ड की गई। पूसा में चार मिमी, आयानगर में 3.8 मिमी और जनकपुरी में दो मिमी वर्षा हुई। मयूर विहार, नरायना और नजफगढ़ में बहुत हल्की बारिश 0.5 मिमी दर्ज की गई। वहीं पालम, जाफरपुर और छतरपुर में इस समय अवधि में बारिश नहीं हुई। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 28 जुलाई से 2 अगस्त तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज धूप से राहत मिलेगी, हालांकि उमस बनी रह सकती है।

नीट यूजी मामला : सीबीआई ने दाखिल की 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आर्थिक अपराध शाखा ने बहुचर्चित नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर दी है। जांच एजेंसी ने इस मामले में कुल 13 आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट पेश की है। सीबीआई द्वारा दाखिल की गई इस चार्जशीट को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष बुधवार को पेश किया जाएगा।

लगाई गईं कड़ी धाराएं

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2); भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(ए); और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 10 के साथ पठित धारा 3, 4, 5 और 11 के तहत दर्ज किया गया है।

फास्ट ट्रैक अदालत आज करेगी सुनवाई

न्यायिक हिरासत में हैं आरोपी

इस मामले में नामजद सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।

यश यादव, मांगीलाल बीवाल, दिनेश बीवाल, विकास बीवाल , शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी ,तेजस हर्षद कुमार , डॉ. मनोज शिरूरे , शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर , मनीषा वाघमारे , मनीषा मंधारे , मनीषा संजय हवलदार।

47 एनटीए अधिकारी निलंबित

सीबीआई ने अदालत को स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है। जांच की आंच एनटीए तक पहुंचने के बाद हाल ही में 47 एनटीए अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। बता दें कि इस धांधली को लेकर 12 मई को एक सरकारी अधिकारी की शिकायत पर पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

10 लाख में खरीदा, 12 लाख में बेचा

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, पेपर लीक की इस पूरी कड़ी में आरोपियों ने लाखों रुपये का खेल किया। मुख्य आरोपी मांगीलाल बिवाल ने अपने बेटे विकास बिवाल को नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र दिलाने के लिए शुभम खैरनार से संपर्क किया था। नेटवर्क के तहत शुभम खैरनार ने सबसे पहले यश यादव को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया। इसके बाद यश यादव ने यह पेपर 10 लाख रुपये में मांगीलाल को बेच दिया। मांगीलाल ने यह पेपर सिर्फ अपने बेटे विकास और दिनेश बिवाल को ही नहीं दिया, बल्कि उसने आगे अन्य अभ्यर्थियों को यही प्रश्नपत्र 12-12 लाख रुपये की मोटी रकम में बेचकर भारी मुनाफा कमाया। जांच के दौरान सीबीआई ने मांगीलाल के मोबाइल फोन से लीक प्रश्नपत्र भी बरामद कर लिए हैं, जो अहम सुबूत माने जा रहे हैं।

पेपर लीक बिल पर लोकसभा में आज फिर चर्चा होगी

राहुल बोले- रेपिस्ट की पैरवी करने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया; रिजिजू बोले- चरित्र हनन की कोशिश

नई दिल्ली । लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 मंगलवार को पास नहीं हो सका। दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक लगातार 9 घंटे बिल पर चर्चा हुई। अभी भी कई सांसदों का बोलना बाकी है। रात 11 बजे स्पीकर ने लोकसभा बुधवार 11 बजे तक स्थगित कर दी। अब बिल पर बुधवार को लोकसभा में फिर चर्चा और वोटिंग होगी। वहीं बिल राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। इससे पहले लोकसभा में प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाने पर भी हंगामा हुआ। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने रेपिस्ट की पैरवी करने वाले शख्स को शिक्षा मंत्री बनाया है। यही बात प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में कही, हालांकि उनकी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। सदन में प्रियंका की टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। रिजिजू, निशिकांत दुबे और जोशी ने विरोध किया और कहा कि प्रियंका ने जोशी का चरित्र हनन किया। प्रियंका इस बात का सबूत दें और माफी मांगें।

स्पीकर बोले- मैं प्रियंका से कहूंगा कि बिना तथ्यों के इस तरह की बातें सदन में न करें।

प्रियंका का जवाब- जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर बयान दिया उसका प्रमाण मैं भेज दूंगी।

केसी वेणुगोपाल ने कहा- इन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया है। आप हटा नहीं सकते हैं।

निशिकांत बोले- मैंने नेहरू जी का नाम लिया था और आज भी अपने बयान पर कायम हूं।

प्रह्लाद जोशी ने कहा- मेरे बारे में जो बोला गया उस पर मुझे पहले से नहीं बताया गया।

स्पीकर ने टोका- सदन में इस बिल पर ही चर्चा होगी। आप सिर्फ विधेयक पर ही बोलें।

इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं, जुमले देती है। दोपहर का सत्र शुरू होने पर स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि मैंने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहे तो समय बढ़ सकते हैं।

इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से बात की है। अब 8 घंटे चर्चा होगी। जरूरत होगी तो हम 10 घंटे भी चर्चा को तैयार हैं।

भारत की पाकिस्तान को दो टूक, खारिज किए पीओके के के चुनाव, कहा- यह अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इन चुनावों से जुड़ी खबरें देखी हैं और यह पूरी कवायद पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश है। रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें देखी हैं। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश, जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जो इस समय पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे में हैं, भारत के अभिन्न अंग हैं।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'यह मौजूदा दिखावटी चुनावी प्रक्रिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर पर्दा डालने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को छिपाने की एक कोशिश मात्र है।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शन वहां के लोगों के आर्थिक शोषण, उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने और प्रशासनिक दमन का सीधा परिणाम हैं। भारत-चीन सीमा व्यापार पर रणधीर जायसवाल ने कहा, 'अगस्त 2025 में, दोनों पक्षों ने तीन निर्दिष्ट व्यापारिक बिंदुओं, यानी लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की थी।' उन्होंने बताया, 'विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 27 से 28 जुलाई तक चीन की आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने बीजिंग में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान से मुलाकात के साथ की। प्रवक्ता जायसवाल ने बताया, 'उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के लिए दोनों नेताओं के मार्गदर्शन के कार्यान्वयन को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके बाद, विदेश सचिव ने चीन को विदेश मामलों की उप मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों पर समग्र रूप से चर्चा की और व्यापार और आर्थिक संबंधों, संस्कृति और जन-जन आदान-प्रदान के माध्यम से पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों सहित, भारत और चीन को सहोदार और एक-दूसरे के लिए विकास के अवसर मानने वाले दोनों नेताओं के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के साधनों पर विचार-विमर्श किया। 'उन्होंने बताया, 'दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को स्वीकार किया। विदेश सचिव ने चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन की 14वीं राष्ट्रीय समिति के उप महासचिव हांग लियांग से भी मुलाकात की। आज, विदेश सचिव ने राष्ट्रीय अकादमी, केंद्रीय पार्टी स्कूल के उपाध्यक्ष ली येंटांग से मुलाकात की।' उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने उन क्षेत्रों या संभावित अवसरों पर चर्चा की, जहां दोनों पक्ष सहयोग कर सकते हैं।

नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें - सुप्रीम कोर्ट

छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई हो

नई दिल्ली ।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही, पात्र छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरन कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छात्रों पर पुलिस की कथित ज्यादती के आरोप प्रथम दृष्टया निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। अदालत ने कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच के लिए आगे चलकर स्वतंत्र समिति या विशेष जांच दल के गठन पर भी विचार किया जा सकता है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उन सभी राज्यों को निर्देश दिया, जहां प्रदर्शन हुए थे, कि सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों से जुड़ा डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जबरन कार्रवाई से राहत केवल उन छात्र प्रदर्शनकारियों को मिलेगी, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर लागू नहीं होगी। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कहा कि सुनवाई पूरी होने तक पात्र छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नाबालिगों और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वालों को रिहा करने के आदेश

राज्यों से भी मांगा गया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस की कथित ज्यादती के आरोपों के साथ-साथ प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 200 से अधिक पुलिसकर्मियों के मामलों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है या अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई की है, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कदम उठाए जाने चाहिए।

सीजेपी की केंद्र सरकार को दो टूक चेतावनी: एफआईआर वापस नहीं ली तो फिर सड़कों पर उतरेगा युवा, देशव्यापी आंदोलन की दी धमकी

नई दिल्ली। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्र सरकार को एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है। पार्टी ने मंगलवार को कहा कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो वे अपना देशव्यापी आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे। पार्टी का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को 'हथियार' बनाकर प्रदर्शनकारियों को निशाना बना सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बढ़ी चिंता

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए और बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। लेकिन सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास का कहना है कि यह आदेश 'देश भर में खतरे की घंटी' की तरह है, क्योंकि सरकार इसका इस्तेमाल शांतिपूर्ण असंतोष को दबाने के लिए कर सकती है।

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

सीजेपी के अनुसार, भारत सरकार ने 25 जुलाई 2026 को युवाओं को आश्वासन दिया था कि सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और किसी भी प्रदर्शनकारी को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसी भरोसे पर आंदोलन वापस लिया गया था। प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि सरकार का रुख उस पवित्र आश्वासन के बिल्कुल उलट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के वकीलों ने अदालत में इस आदेश का विरोध नहीं किया, जो कि 'छलपूर्ण' तरीका है।

आज खत्म हो रही है समय सीमा

पार्टी ने सरकार को दी गई मोहलत की याद दिलाते हुए कहा कि आज वह समय सीमा समाप्त हो रही है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने भी समझौते के उल्लंघन का दावा करते हुए कहा कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मांग की कि सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाएं, अन्यथा छात्र और युवा एक बार फिर देश की सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

पेपर लीक के खिलाफ था आंदोलन

गौरतलब है कि सीजेपी ने 20 जून से पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर मोर्चा खोल रखा था, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग थी। 20 जुलाई को निकाले गए 'संसद मार्च' के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जहां पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था। इस संघर्ष में प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ 118 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अब एक बार फिर आंदोलन की सुगबुगाहट ने राजधानी में हलचल तेज कर दी है।

उड़ी में एलओसी पर जोरदार धमाका! माइन ब्लास्ट में सेना के 2 जवान घायल

श्रीनगर।

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर से मंगलवार को एक चिंताजनक खबर सामने आई है। देश की सुरक्षा में दिन-रात तैनात भारतीय सेना के दो जवान नियंत्रण रेखा के पास हुए एक जोरदार माइन विस्फोट में घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सेना ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। सरकारी अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा उड़ी के कमालकोट सब-सेक्टर में स्थित अपर गढ़ फॉरवर्ड पोस्ट के करीब हुआ। यह बेहद संवेदनशील इलाका है और यहां 12 इन्फैंट्री ब्रिगेड के तहत 8 राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी तैनात है। यह पूरा क्षेत्र उड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को जब जवान अपनी नियमित गश्त और ड्यूटी पर थे, तभी अचानक एक पुरानी माइन में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में उसकी आवाज सुनी गई। इस विस्फोट की चपेट में आकर दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

आंदोलन के बीच मूंग खरीदी सहित कई मांगों पर कृषि मंत्री कंषाना ने दिया बड़ा आश्वासन, किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात करके किया आश्वस्त

भोपाल । मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति संवेदनशील है और सभी मुद्दों का शीघ्र एवं सकारात्मक समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा मूंग खरीदी सहित अन्य विषयों पर आवश्यक कदम उठाए जाएँ। कृषि मंत्री कंषाना ने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा, जिस पर कृषि मंत्री कंषाना ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र निर्णय लेने का भरोसा दिलाया।

सक्षम भारत

सक्षम भारत की वेबसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।

पट्टी बांधकर संसद क्यों पहुंचे पप्पू यादव? छात्र आंदोलन-पुलिस कार्रवाई पर मोदी सरकार से पूछे सवाल

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सिर पर 'जस्टिस' लिखी पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने छात्र प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग किया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका पहले अन्य जगहों पर उपयोग होता था। उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। अपने बयान में पप्पू यादव ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली पगड़ी एक भ्रष्ट व्यक्ति को पहनाई गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या किसी चोर को इतनी सम्मानित पगड़ी से सम्मानित किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने अपने बयान में दोहराया कि प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ हो रही कार्रवाई पर सरकार को जवाब देना चाहिए और इस पूरे मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और उनके परिवारों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, वह गंभीर मामला है। उन्होंने मांग की कि सरकार सबसे पहले छात्रों से माफी मांगे और कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार पुलिस ने छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य के साथ अन्याय किया है। उनका आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया।